(e) The DDA has imposed annual financial limits to check award of works without call of tenders by officers at various levels, the intention being to minimise award of works in this manner and restrict them to absolutely unavoidable cases.

Production of Sunflower and Soyabean

*380. SHRIMATI BASANTI SARMA: DR. SHRIKANT RAMCHANDRA JICHKAR: Will the Minister of AGRICULTURE be pleased to state:

(a) whether there is a trend to produce more sunflower or to produce more soyabean;

(b) which production is more beneficial to the country, soyabean or sunflower;

(c) what steps are being taken to boost such production; and

(d) what are the States which are performing well and the States which are not performing well in this area?

THE MINISTER OF AGRICULTURE (SHRI BALRAM JAKHAR): (a) There is increasing trend in the production of both sunflower and soyabean in last few years as indicated below:

(Produciton in lakh tons)

Year	Soyabean	Sunflower
1990-91	26.0	8.70
1991-92	24.9	11.90
1992-93	31.1	11.80
1993-94	46.2	13.86 (likely)

(b) Production of both the crops is beneficial for the country. Sunflower produces more oil per ton of sunflower grain in comparison to soyabean. While the soyabean is a foreign exchange earner crop because soya cake is exported after extracting the oil from the grains.

(c) To increase production of both these crops a centrally sponsored Oilseeds Production Programme(OPP) is under implementation in 22 States.The assistance is provided under O.P.P. on production and distribution of seeds, seed minikits, sprinkler sets, improved farm implements, rhyzobium culture, gypsum/ and pyrites and laying out of frontline, general and Integrated Pest Management (IPM) demonstrations on farmers fields.

(d) The important soyabean growing States are Madhya Pradesh, Maharashtra, Rajasthan, Uttar Pradesh and Karnataka. While sunflower is mainly grown in Karnataka, Maharashtra, Punjab, Haryana, Tamil Nadu and Uttar Pradesh. Other States have very little area under soyabean and sunflower.

Proposals from MNUs and NRIs to enter agricultural field

3246. SHRI SATISH PRADHAN: Will the Minister of AGRICULTURE be pleased to state:

(a) whether Government has received proposals from multinational industrial units and NRIs to enter into agriculture field;

(b) if so, what is the number of proposals from multinational companies and NRIs to enter into agriculture field;

(c) whether Government has approved any such proposals, if so, the details thereof;

(d) whether such units will be permitted to purchase land beyond the purview of ceiling limit statute prevailing in the States; and

(e) what are the details in this regard?

THE MINISTER OF STATE IN THE MINISTRY OF AGRICULTURE (SHRI S. KRISHNA KUMAR): (a) to (e) The requisite informaion is being collected and will be laid on the Table of the Sabha.

तालाबों में मत्स्य-पालन

3247. **श्री नारायण प्रसाद गुप्ता:** क्या कृषि मंत्री यह बताने की कृपार करेंगे कि:

(क) क्या यह सच है कि मध्य प्रदेश के मत्स्य विकास विभाग ने माह फरवरी, 1994 में तालाबों में मत्स्य-पालन योजना के अधीन कृषि मंत्रालय को उसकी स्वीकृति के लिए लगभग 4.50 करोड़ रुपए की लागत वाली पांच योजनाएं प्रस्तुत की हैं; और

(ख) यदि हां, तो कृषि-मंत्रालय उपर्युक्त योजनाओं को कब तक अपनी स्वीकृति दे देगा?

कृषि मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री एस. कृष्ण कुमार): (क) जी, नहीं। तथापि, फरवरी, 1994 के दौरान मध्य प्रदेश सरकार से लगभग 4.35 करोड़ रुपए की लागत के अन्तर्देशीय मत्स्य विपणन योजना के संवर्धन के लिए पांच इकाइयों के वास्ते प्रस्ताव प्राप्त हुए हैं।

(ख) इन प्रस्तावों की स्वीकृति करना सम्भव नहीं हुआ है क्योंकि इनके वर्तमान स्तर पर अन्तर्देशीय मत्स्य विपणन की योजना को अभी रोक दिया गया है।

कृषि और गायों की नस्ल सुधार के लिए प्रोत्साहन

3248. **श्री गोपाल सिंह जी. सोलंकी:** क्या कृषि मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) सरकार ने गुजरात में कृषि और गायों की नस्ल में सुधार करने को प्रोत्साहन देने के लिए क्या-क्या कदम उठाए हैं;

(ख) आठवीं पंचवर्षीय योजना अवधि के दौरान इस प्रयोजनार्थ कितनी धनराशि आवंटित की गई है;

(ग) क्या सरकार गुजरात के किसानों को कृषि-क्षेत्र में इजरायली तकनीक उपलब्ध कराने का विचार रखती है; और

(घ) यदि हां, तो इस सम्बन्ध में क्या प्रयास किए जा रहे हैं?

कृषि मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री अरविन्द नेताम): (क) और (ख) गीर नस्ल की गायों के विकास के लिए "राष्ट्रीय सांड उत्पादन कार्यक्रम" के अन्तर्गत गुजरात सरकार को 1993-94 में 188.00 लाख रुपए का सहायता अनुदान दिया गया था। उच्च उत्पादन तथा खाद्य एवं वाणिज्यिक फसलों की उत्पादकता बढ़ाने के लिए विभिन्न विकास कार्यक्रमों के अन्तर्गत वित्तीय प्रोत्साहन भी दिए जाते हैं। आठवीं योजना के अन्तर्गत, गुजरात के लिए कृषि, पुशपालन तथा संबंधित कार्यकलापों के लिए 732 करोड़ रुपए का परिव्यय रखा गया है।

(ग) और (घ) जल प्रबन्ध की प्रोद्योगिकी को प्राप्त करके कृषि में सुधार करने, ड्रिप सिंचाई, ग्रीनहाऊस, पुष्पोत्पादन तथा नाशवान जिन्सों के कटाई पश्चात् रख-रखाव आदि के लिए गुजरात सरकार ने इजराइली फर्मों/एजेन्सियों के साथ कुछ समझौता ज्ञापनों पर हस्ताक्षर भी किए हैं।

दूध का उत्पादन

3249. **श्री गोपाल सिंह जी. सोलंकी:** क्या कृषि मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) दूध की प्रतिदिन प्रति व्यक्ति उपलब्धता कितनी है;

(ख) आठवीं पंचवर्षीय योजनावधि के दौरान दुग्ध-उत्पादन का राज्य-वार क्या लक्ष्य निर्धारित किया गया है;

(ग) गत तीन वर्षों के दौरान वर्ष-वार और राज्य-वार दुग्ध उत्पादन बढ़ाने हेतु बनाए गए मुख्य नियंत्रण क्षेत्रों, केन्द्र द्वारा प्रायोजित योजनाओं का ब्यौरा क्या है;

(घ) आठवीं पंचवर्षीय योजनावधि के दौरान ऐसी योजनाओं के लिए अलग-अलग दी गई धनराशि का योजना-वार और राज्य-वार ब्यौरा क्या है; और

(ङ) आठवीं पंचवर्षीय योजनावधि के दौरान निजी तथा सहकारी क्षेत्र सहित डेरी उद्योग में किए जाने वाले निवेश का ब्यौरा क्या है?

कृषि मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री अरविन्द नेताम): (क) वर्ष 1992-93 के दौरान दूध की प्रतिदिन प्रति व्यक्ति उपलब्धता 182 ग्राम थी।

(ख) आठवीं पंचवर्षीय योजना के राज्य-वार लक्ष्य विवरण-I में दिए गए हैं (नीचे देखिए)

(ग) विगत तीन वर्षों के दौरान दूध का उत्पादन बढ़ाने के लिए केन्द्र द्वारा प्रायोजित योजनाओं के लिए किया गया राज्य-वार व्यय अनुपत्र-2 पर दिया गया है। (देखिए परिशिष्ट 171, अनुपत्र सं. 54)

(घ) दूध के उत्पादन से सम्बन्धित योजनाओं के लिए आठवीं पंचवर्षीय योजना के परिव्ययों का ब्यौरा विवरण II पर दिया गया है। (नीचे देखिए)

(ङ) आठवीं योजना के दौरान, पशुपालन तथा डेरी विकास के लिए केन्द्रीय क्षेत्र के 900 करोड़ रुपये को मिलाकर सार्वजनिक क्षेत्र में 2838.32 करोड़ रुपये के परिव्यय का प्रावधान किया गया है।

विवरण-I

आठवीं योजना (1996-97) के दौरान देश में दुग्ध उत्पादन का राज्य-वार निर्धारित लक्ष्य

क्र.सं.	राज्य/संघ राज्य क्षेत्र	आठवीं योजना के लिए दुग्ध उत्पादन का लक्ष्य ("00 टन)
1	2	3
1.	आन्ध्र प्रदेश	4400
2.	अरुणाचल प्रदेश	44
3.	असम	850
4.	बिहार	3720
5.	गोवा	30